हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 09 | देहरादून, शुक्रवार, 24 जून, 2022 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 08

भारत सरकार की कुपोषण के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में विभाग लगातार कर रहा काम : रेखा आर्या

3

धामी ने पीएम से शिष्टाचार भेंट कर मांगी कई योजनाओं की स्वीकृति

जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने व राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की राज्य में शाखा स्थापित किये जाने का अनुरोध किया

पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र संचालन व मानस खण्ड मंदिर माला मिशन की स्वीकृति का भी किया अनुरोध

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिये देवभूमि उत्तराखण्ड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखण्ड के लिये जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून, 2022 के आगे बनाए रखने, उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने, कुमांऊ मण्डल के पौराणिक मन्दिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से "मानस खण्ड मन्दिर माला मिशन" को स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारू संचालन के लिये संबंधित को निर्देशित किये जाने के साथ ही टीएचडीसी इण्डिया लि0 की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश के 25 प्रतिशत अंशधारिता को उत्तराखण्ड राज्य को स्थानान्तरित करने में केंद्र से सहयोग का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य, देश के फार्मास्यूटिकल हब के रूप में उभर रहा है। भारत में कुल उपभोग होने वाली दवाओं में उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित औषधि निर्माण इकाईयों की लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य में स्थापित 03 प्रमुख औद्योगिक संकुलों यथा-देहरादून, हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर में 300 से अधिक फार्मास्यूटिकल निर्माण इकाइयां स्थापित हैं जो 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहीं है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने का अनुरोध किया। इससे राज्य में फार्मास्यूटिकल शोध को बढावा मिलेगा। उक्त संस्थान की स्थापना हेतु वांछित भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में एयरस्ट्रिप से फिक्सडविंग (वायुयान) हवाई सेवा संचालित किये जाने हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारू संचालन के लिये सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 05 वर्षों यथा 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी थी। परंतु संरचनात्मक परिवर्तन, न्यून उपभोग आधार, राज्य में सेवा का अपर्याप्त आधार सहित अन्य कारणों से जीएसटी लागू होने के उपरांत राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि जून, 2022 के पश्चात अग्रेत्तर वर्षों के लिए बढ़ाये जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ को मास्टर प्लान तैयार कर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसी भांति प्रदेश के कुमांऊ मण्डल के पौराणिक मन्दिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से "मानस खण्ड मन्दिर माला मिशन" की स्वीकृति दिये जाने का अनुराध किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि टीएचडीसी इण्डिया लि० भारत सरकार की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 47 (3) के अनुसार उत्तर प्रदेश द्वारा विभाजन की तिथि तक टीएचडीसी इण्डिया लि० में किये गये पूंजीगत निवेश के आधार पर उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरित होना चाहिए क्योंकि टीएचडीसी इण्डिया लि० का मुख्यालय उत्तराखण्ड राज्य में स्थित है। टीएचडीसी इंडिया लि0 की लगभग 70 प्रतिशत परियोजना उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। उक्त परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली पुनर्वास, कानून व्यवस्था तथा अन्य सामाजिक एवं पर्यावरण सम्बन्धी चुनौतियों का सामना भी उत्तराखण्ड राज्य को करना पड़ता है। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा वर्ष 2012 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-131 के अन्तर्गत टीएचडीसी इण्डिया लि० में उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड राज्य की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी हेतु मूल वाद संख्या 05 / 2012 मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित किया गया था जो सम्प्रति विचाराधीन है।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से टीएचडीसी इण्डिया लि की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश के 25 प्रतिशत अंशधारिता को उत्तराखण्ड राज्य को स्थानान्तरित करने में केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ऊर्जा इत्यादि क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास कर रहा है। उनकी अपेक्षा अनुसार वर्ष 2025 में राज्य के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखण्ड के लोहाघाट के समीप स्थित मायावती आश्रम आने के लिये भी अनुरोध किया।

चमोली में दरका पहाड़, कर्णप्रयाग-ग्वालदम हाईवे मौणाछीड़ा में बंद

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

नारायणबगड़-बगोली के बीच इन दिनों हाईवे चौड़ीकरण कार्य के तहत पहाड़ी कटिंग का काम चल रहा है। बृहस्पतिवार को यहां काम के दौरान कर्णप्रयाग-ग्वालदम हाईवे पर मौणाछीड़ा के पास पहाड़ी दरकने से हाईवे बंद हो गया। हाईवे बंद हो जाने से यहां बरात की गाड़ियों समेत कई यात्री वाहन फंस गए। देर शाम सात बजे हाईवे खोल दिया गया।

बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे पहाड़ी की कटिंग के दौरान अचानक पहाड़ी दरकने से हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा व बोल्डर आ गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे वाहन व बरात की कई गाड़ियां वहीं पर फंस गईं। ऐसे में नारायणबगड़ के झिंझौणी से आदिबदरी के रंडोली गांव जा रही बरात की कुछ गाड़ियां नारायणबगड़ से परखाल होते हुए कफारतीर सड़क मार्ग से नलगांव तक करीब 45 किमी की अतिरिक्त दूरी तय कर हाईवे पर पहुंचीं और तब गंतव्य को रवाना हुईं।

देहरादून में 92.72 लाख रुपये की ठगी, फ्लैट दिलाने के नाम पर दो लोगों से ठगे पैसे

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादूनः फ्लैट दिलाने के नाम पर बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर लाखों रुपये ठगने वाले एसए बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक प्रेमचंद शर्मा के खिलाफ राजपुर थाने में दो और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस बार रकम 92 लाख 72 हजार रुपये हैं। आरोपित ने आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर व कर्मचारियों के साथ मिलकर श्री राम पुरम कांवली रोड निवासी अतुल शर्मा से साढ़े 48 लाख रुपये और विजय पार्क निवासी आशा रावत से 44 लाख 22 हजार रुपये ठग लिए।

आरोपित ने राजपुर रोड पर आवासीय योजना आर्टिगो रेसीडेंसी में फ्लैट दिलाने के नाम पर बैंक से लोन करवाया औरलोन खुद ही हड़प गया। इसमें आइसीआइसीआइ बैंक के तत्कालीन मैनेजर व कर्मचारियों की मिली भगत भी पाई गई है। राजपुर के थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि प्रेमचंद शर्मा के खिलाफ अब तक बैंक अधिकारियों व कर्मचारी से मिली भगत कर ठगी करने के छह मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

इन पांच टिप्स से आप अपने बच्चों को मेन्टल हेल्थ से दूर कर सकते है

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

जागरूकता और स्वीकृति :

कई बार जब बच्चे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो उनकी दैनिक लय जैसे व्यवहार, मनोदशा, नींद और भूख बदल जाती है। आम तौर पर बोलते हुए, विशेष रूप से व्यवहार में बदलाव जैसे मनोदशा या क्रोध के प्रकोप को व्यावहारिक तरीके से निपटाया जाता है। मतलब उन्हें बुरे व्यवहार के रूप में देखा जाता है और विशेषाधिकारों को छीनकर, फटकार, आलोचना, डांट और कभी-कभी उन्हें मारकर बच्चे को अनुशासित करने का प्रयास किया जाता है। इससे यह और बदतर हो जाता है.इसलिए सबसे पहले यह जान लें कि बच्चे के व्यवहार में बदलाव आंतरिक अशांति का संकेत है। माता-पिता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि तनाव, अनिश्चितता, भय, COVID प्रेरित चिंता और स्कूलों और दिनचर्या में व्यवधान के कारण बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में वृद्धि हुई है।

भावनात्मक रूप से बाहर आने के लिए समय दे :

हो सकता है कि बच्चा बेड से उठना न चाहे या केवल जंक फूड खाना चाहता है. हालांकि, बच्चे जंक फूड मांग रहे होंगे, क्योंकि वे अब रेगुलर खाना नहीं खा सकते, क्योंकि उनकी भूख कम हो गई है. वे आरामदेह भोजन की तलाश में हैं जो चिंता को कम करने और मूड चेंज करने में मदद करता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनकी हर इच्छा को पूरा करें, बल्कि उनका स्पोर्ट करने की कोशिश करें. अपने बच्चे को चीजों को करने के लिए प्रेरित करने के बजाय परिस्थितियों से उबरने के लिए टाइम और जगह दें. आपका बच्चा जान-बूझकर कोई खास तरीके से पेश नहीं

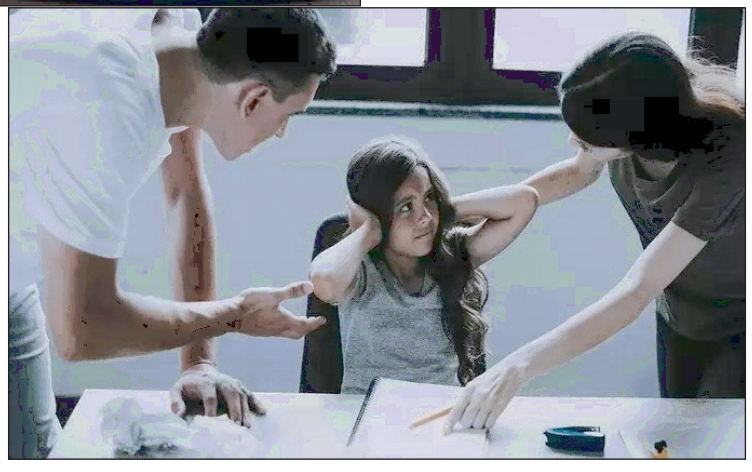

आ रहा है. डॉ. सेन ने कहा कि बच्चे भी यह सोचकर बहुत अपराध बोध से गुजरते हैं कि वे दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं.

सुनाने के लिए नहीं, सुनने के लिए सुनो :

भावनात्मक रूप से सुरक्षित स्थान बनाने का मतलब ये भी है कि बच्चे को न्याय किए जाने, आलोचना किए जाने के डर के बिना व्यक्त करने देना और यह सोचने से बचें कि 'मेरे माता-पिता हल या भाषण देंगे'. जैसे ही बच्चे अपनी चुनौतियां बताना शुरू करते हैं, पेरेंट्स तुरंत हल तलाशने लगते है. वह अच्छी जगह से आता है, लेकिन याद रखें कि बच्चा सहानुभूति की तलाश में हैं. अपने दिल से सुनें, जानकारी को और भावना को समझें.

तुम, मैं, और हम' का नजरिया अपनाएं :

न तो पेरेंट्स और न ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यह तय कर सकते हैं कि बच्चे के लिए अच्छा क्या है. कोई भी फैसला बच्चे के साथ मिलकर ही लेना होगा. उदाहरण के लिए, यदि माता-पिता अपने बच्चे के लिए बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो उन्हें ऑप्शन देना चाहिए जैसे, क्या आप किसी पार्क में जाना चाहते हैं, अपने दोस्त के घर या दादी के घर जाना चाहते हैं. 5 या 6 साल की उम्र के बच्चे, अपने विचारों को शब्दों में बयां नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वे चुन सकते हैं. यदि वे चुनाव करते हैं, तो वे बहुत अधिक सशक्त महसूस करेंगे. आप बच्चे से पूछ सकते हैं, 'आपको क्या लगता है कि आपकी क्या मदद करेगा?' या 'हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं?' उदाहरण के लिए, एक बच्चा मोबाइल पर बहुत अधिक समय बिता रहा है. ऐसे में बच्चे से अपने संबंध के आधार पर, आप कह सकते हैं, 'मैंने देखा है कि जब आप स्क्रीन पर घंटों बिताते हैं, तो आप सुस्त हो जाते हैं. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?' और फिर मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करें.

धैय बनाए, तुलना न करें तुलना :

किसी भी मानसिक बीमारी का इलाज एक यात्रा की तरह होता है, जिसमें मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य की जरूरत होती है. उदाहरण के लिए, एक बच्चा संगीत सीखना चाहता है क्योंकि इससे उसे शांति मिलती है, लेकिन वह रेगुलर क्लास लेने में सक्षम नहीं हो सकता है. ऐसे में उसको डांटने की बजाय कहें, कभी-कभी क्लास लेना सही है. अगर ये युक्ति काम नहीं करती, तो दूसरा उपाय तलाशें.बच्चे जब भावनात्मक कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं, उस समय इस बात का विशेष असर होता है कि उन्हें कैसे समझा जा रहा है और उन्हें कैसा माहौल दिया जा रहा है. उदाहरण के लिए, ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान, कुछ बच्चों को ध्यान लगाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. बदले में, टीचर शिकायत करेंगे, माता-पिता उन्हें डाटेंगे, और देर-सवेर आपको एहसास होगा कि बच्चा भावनात्मक स्थिति या अवसाद या चिंता जैसे विकार से पीड़ित है. चिंता इस बात की है कि बच्चा इन नई परिस्थितियों के अनुकूल किस तरह हो सकता है.

उत्तराखंड में अब 'वेस्ट' नहीं जाएगा गिला कूड़ा, गीले कूड़े से बनेगी खाद

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड में कूड़ा निस्तारण बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन अब कूड़े का निस्तारण कर उसे उपयोगी बना लिया गया है. जी हां, हर्रावाला में कूड़ा निस्तारण के लिए कंपोस्ट मशीन लगाई गई है. जिसके जरिए गीले कूड़े से जैविक खाद बनाई जा रही है. यह खाद 15 दिनों में बनकर तैयार हो रही है, जो खेती के लिए भी उपयोगी साबित होगी और कूड़े की समस्या कुछ हद तक दूर भी होगी.

बता दें कि उत्तराखंड में यह पहली कंपोस्ट मशीन है, जो देहरादून के हर्रावाला में लगाई गई है. इस कंपोस्ट मशीन का शुभारंभ 25 जून को मेयर सुनील उनियाल गामा करेंगे. वेस्ट वॉरियर्स के अध्यक्ष नवीन सडाना ने बताया कि साल 2018 में नगर

निगम के सहयोग से हर्रावाला के वार्ड 97 में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी वेस्ट वॉरियर्स ने ली थी. अपने इस वार्ड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वॉरियर्स लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस साल से खाद बनाने के लिए गीला कचरा अलग होकर उनके पास पहुंच रहा है. उससे खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. उसी के लिए एक हजार किलो प्रतिदिन की क्षमता वाली कंपोस्ट मशीन लगाई गई है. इस मशीन के जरिये हर्रावाला के सभी परिवार अपने घर का गीला कचरा गाड़ी को देते हैं. जब गाड़ी गीला कचरा साइट पर लेकर पहुंचती है तो गीले कचरे को बुरादे में मिलाकर मशीन में डाला जाता है. जो मशीन के अंदर अलग-अलग चेंबर होने के बाद करीब 15 दिनों में यह खाद बनकर बाहर आ जाती है. इस मशीन को लगे करीब एक महीना हुआ है. नवीन सडाना ने बताया कि वर्तमान में करीब 400 किलो गीला कचरा जो खाने से बचा होता है, वो यहां पहुंच रहा है. इस मशीन की क्षमता एक हजार किलो की है. लगातार कोशिश की जा रही है कि यह और लोगों तक भी पहुंचे. पूरे देहरादून में यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, जहां यह मशीन लगी है.वहीं,

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि हर्रावाला वार्ड नंबर 97 में कंपोस्ट मशीन लगाई गई है, जो कि मैन्युअल और ऑटोमेटिक संचालित हो सकती है. जिसकी क्षमता प्रतिदिन एक टन कचरे की है. इस मशीन से 15 दिन के भीतर खाद तैयार की जाएगी. इसके संचालन के बाद हर्रावाला क्षेत्र में काफी कूड़ा प्रोसेस होगा. अविनाश खन्ना ने कहा कि देहरादून में यह पहला प्रोजेक्ट है. .उन्होंने कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता है और इस तरह के प्रोजेक्ट अन्य वार्डों में लगा दें तो नगर निगम के कूड़े की समस्या कई हद तक कम तो होगी ही, साथ ही इस कूड़े से बनने वाली खाद से रुपए भी कमाए जा सकते हैं.

भारत सरकार की कुपोषण के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में विभाग लगातार कर रहा काम : रेखा आर्या

बाल विकास मंत्रालय की ओर से किया गया संयुक्त जोनल सेमिनार का आयोजन

■ बआँगनवाड़ी केंद्रों के कारण कुपोषण के स्तर को बहुत हद तक किया जा सका है नियंत्रित-रेखा आर्या

■ महिलाओं के लिए हर जनपद एवं हर राज्य में महिलाओं से संबंधित योजनाओं को कराया जाएगा एक हब के रूप में उपलब्ध-रेखा आर्या

■ मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना के अंतर्गत हफ्ते में चार दिन दिया जाता है 2 लाख 37 हज़ार बच्चों को 100 एमएल दूध- रेखा आर्या

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हरिद्वार स्थित एक निजी होटल में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर भारत राज्यों के आकांक्षी जनपदों का संयुक्त जोनल सेमिनार तथा योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंजू पारा महेंद्र भाई जी राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ,उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी , हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी, तथा उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत जी ने शिरकत की।साथ ही इस सेमिनार में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं जम्मू और कश्मीर के जन प्रतिनिधियों तथा जिलाधिकारियों तथा विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सेमिनार का उद्देश्य उत्तर भारतीय राज्यों के आकांक्षी जनपदों में महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा, बेस्ट प्रैक्टिसेज की साझेदारी करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ।

महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से प्रदेश में योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन एवं नई योजनाओं के द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण तथा महिला सशक्तीकरण की दिशा में नित नए आयाम प्राप्त किये जा रहे हैं। पोषण अभियान को राज्य में प्रभावी बनाते हुए मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना के अंतर्गत 2 लाख 37 हज़ार बच्चों को 100 एमएल दूध हफ्ते में चार दिन दिया जाता है तथा मुख्यमंत्री बाल पलाश योजना के अंतर्गत सप्ताह में दो दिन अंडा और दो दिन केला दिया जा रहा है तथा इस प्रकार भारत सरकार की पोषण अभियान के ताल से ताल मिलाकर कुपोषण के विरुद्ध प्रतिबद्ध हैं। इसी के साथ बच्चे के स्वास्थ्य के साथ ही माँ के स्वास्थ्य को भी प्रमुखता दी गयी है इसीलिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रधान मंत्री मातृवन्दना योजना के सम्पूरक के रूप में महिला पोषण योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत महिलाओं को भी सप्ताह में दो दिन अंडा और दो दिन केला प्रदान किया जा रहा है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण अभियान दोनों के उद्देश्यों को साधते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महालक्ष्मी योजना भी चलाई जा रही है जिसमें प्रसवोपरांत अतिरिक्त देखभाल हेतु आवश्यक सामग्रियों से युक्त किट का वितरण बालिका जन्म पर किया जाता है। माननीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वात्सल्य योजना के अंतर्गत कोविड से प्रभावित 4100 से अधिक बच्चों को प्रतिमाह 3000 की सहायता राशि दी जा रही है। तथा उनकी आवश्यकतानुसार उनको विभिन्न विभागीय सेवाओं से आच्छादित किया जा रहा है तथा जनपद में जिलाधिकारियों को इस हेतु नोडल बनाया गया है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त पहल से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बाल वाटिका को संचालित करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य हो सकता है। सांसद हरिद्वार डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि समाज के अंतिम तबके के प्रत्येक व्यक्ति को सफल बनाने हेतु चिकित्सा, शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास पर सबसे अधिक ध्यान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है । राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास भारत सरकार मंजू पारा महेन्द्र भाई ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के पोषण तथा महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु नीतिगत हस्तक्षेप भारत सरकार के स्तर पर किये गए हैं।

वहीं इस अवसर पर वात्सल्य योजना के अंतर्गत 4000 प्रभावित बच्चों को प्रति बच्चा 3000 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल रुपये 2 करोड़ 40 लाख , माह अप्रैल एवं मई की किश्त के रूप में इंडसइंड बैंक के सहयोग से एक क्लिक पर उनके खातों में डी0बी0टी0 द्वारा प्रेषित की गई तथा योजना की एक वीडियो फ़िल्म के माध्यम से अन्य राज्यों से आये प्रतिभागियों को योजना की जानकारी दी गयी। साथ ही उपस्थित लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया ।

इस अवसर पर अध्यक्ष एवं सदस्य बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड, सचिव महिला एवं बाल विकास हरि चंद्र सेमवाल जी, उत्तर प्रदेश से जिलाधिकारी सोनभद्र एवं बलरामपुर, जिलाधिकारी हरिद्वार, जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर तथा राज्यों के प्रशासनिक एवं विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड से उपनिदेशक एस0के0 सिंह , राज्य परियोजना अधिकारी अखिलेश मिश्रा, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी के अतिरिक्त अकादमिक तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

देहरादून नगर निगम की मॉनसून से निपटने की पूरी तैयारी, जलभराव से मिलेगी निजात

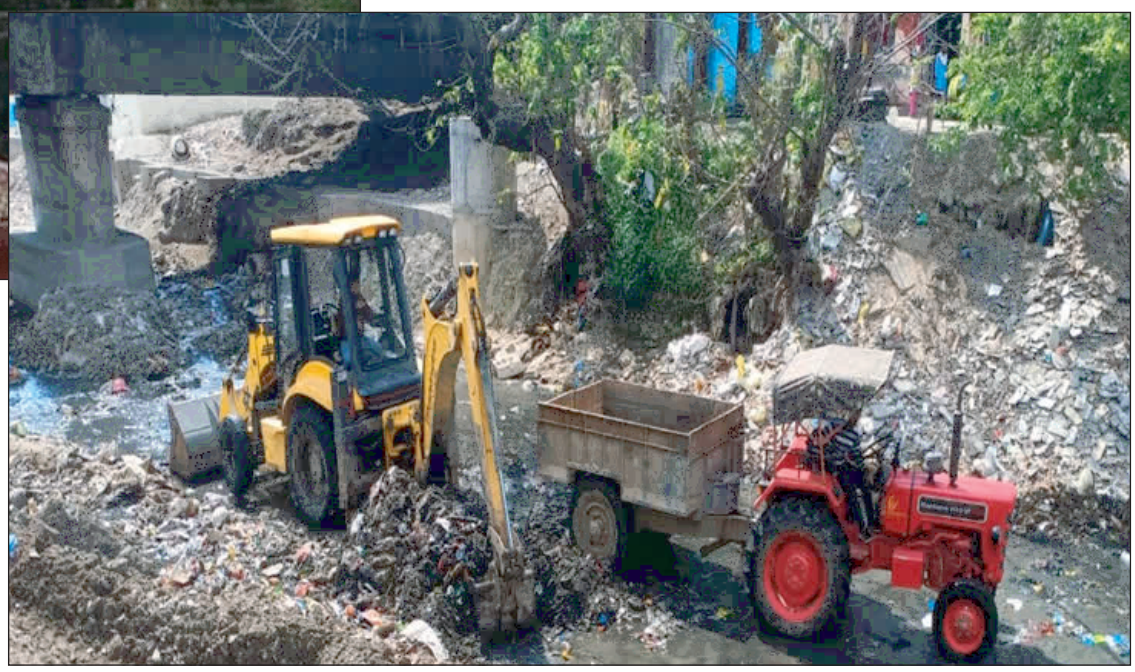

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून नगर निगम के तहत 40 से ज्यादा बड़े नाले हैं, जो बरसात के दिनों में चोक हो जाते हैं. ऐसे में बारिश का गंदा पानी कॉलोनियों में घुस जाता है. जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लिहाजा, दून नगर निगम की अपनी तैयारियों पुख्ता करने में जुटा है.

देहरादून नगर निगम दावा कर रहा है कि मानसून आने से पहले शहर के 95 प्रतिशत मुख्य नालों की सफाई की जा चुकी है. साथ ही रिस्पना और बिंदाल नदियों में काफी हद तक सफाई खत्म हो चुकी है. वहीं, 25 जून तक शहर के सभी नदी-नालों की सफाई का काम निपटा दिया जाएगा. साथ ही इस साल नगर निगम की टीम ने मुख्य उन नालों को चिन्हित किया है, जिनके कारण कॉलोनियों में पानी भरता है. बरसात के दिनों में अगर किसी कॉलोनी में आपदा जैसी स्थिति आती है तो नगर निगम परिसर में आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है. जिसमें 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात की गई है. साथ ही बार नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया जाएगा. नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि नगर निगम की ओर से शहर के सभी प्रमुख नदी नालों की सफाई गतिमान है, करीब 95 प्रतिशत नालों की सफाई हो चुकी है और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले चार-पांच दिनों में बाकी बचे नदी नालों की सफाई पूरी की जाए. इसके साथ ही आपदा का 24x7 कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है. आपदा को लेकर नगर निगम में बैठक भी की गई थी. एक क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई है. इसके माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो उसका समाधान करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकें. उन्होंने बताया कि शहर के वो नाले और नदी जिनके कारण कॉलोनियों में पानी भरने की समस्या आती है, ऐसे नदी-नालों को चिन्हित करते हुए सफाई प्राथमिकता से कराई गई है. साथ ही अगर कंपनियों में आपदा जैसी स्थिति आती है तो नगर आयुक्त ही जिम्मेदार होंगे.हर साल नगर निगम की ओर से बरसात से पहले नदी नालों की सफाई को लेकर दावा किया जाता है, लेकिन जब मॉनसून से भारी बारिश होती है तो शहर की कई कॉलोनियों ऐसी हैं, जो जलमग्न हो जाती हैं और कॉलोनीवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब देखने वाली बात रहेगी कि मानसून से पहले नगर निगम की ओर से की गई तैयारी कितनी सफल होती है या फिर मानसून की बारिश होने के बाद निगम के सभी सभी दावे खोखले साबित होंगे.

2050 तक 250 करोड़ लोग हो सकते हैं बहरे, घातक है हेडफोन

महविश फ़िरोज़
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

स्कूल हो , यूनिवेर्सिटी हो , घर में स्टडी रूम हो या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स , युवा किसी भी शहर , राज्य या देश के हों सबसे ज्यादा ईपी यानी ईयर पीस या यूँ कहे हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने घर परिवार में भी नज़र दौड़ाएंगे तो बच्चे और स्टूडेंट्स के साथ साथ महिलाएं भी कानों में इयरपीस या हेडफोन लगाकर काम करती है। कहने को तो ये मनोरंजन है जिसमें किसी दूसरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है लेकिन जल्द ही इसका नतीज़ा बेहद ख़ौफनाक नज़र आने वाला है।

फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिसर्च से पता चला है कि फ्रांस में चार में से एक व्यक्ति को सुनने में परेशानी हो रही है। वे धीरे-धीरे बहरे होते जा रहे हैं। मतलब वहां की 25% आबादी इससे प्रभावित हो रही है।

डिप्रेशन और शोर से लोग हो रहे हैं बहरेपन का शिकार

पहली बार फ्रांस में इस तरह की रिसर्च बड़े लेवल पर की गई है, जिसमें 18 से 75 वर्ष की उम्र के 1,86,460 लोगों का शामिल किया गया था। रिसर्च करने वालों का मानना है कि पहले केवल छोटे लेवल पर रिसर्च की गई थी, लेकिन इस बार की गई रिसर्च के मुताबिक लोगों को सुनने में समस्या लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन व डिप्रेशन व तेज आवाज के संपर्क में आने के कारण हो रहा है।

2050 तक बढ़कर 250 करोड़ लोग हो सकते हैं बहरे

रिसर्च में पाया गया है कि कुछ लोगों में शुगर और डिप्रेशन की वजह से सुनने की समस्या हो रही है। वहीं कुछ लोगों को अकेलेपन, शहरी शोर और हेडफोन का यूज करने के कारण परेशानी हो रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, दुनिया में लगभग 150 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में सुनने में समस्या महसूस कर रहे हैं। यह संख्या 2050 तक बढ़कर 250 करोड़ होने की संभावना है। इसलिए इसे स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखा जा रहा है।

फ्रांस में 37% लोग ही करते है हियरिंग एड इस्तेमाल

फ्रांस में महज 37% लोग ही हियरिंग एड इस्तेमाल करते हैं। धूम्रपान करने वाले और उच्च BMI वाले लोग भी हियरिंग एड का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए पिछले साल, फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने फ्री में श्रवण यंत्र लोगों को उपलब्ध कराए गए थे। हियरिंग एड के लिए बीमा का भी प्रावधान किया गया है।न्यूज़ वायरस की आपसे गुज़ारिश है कि जितना हो सके कम से कम हेडफोन और ईपी का इस्तेमाल करें। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने फायदे देते हैं उनका दुष्परिणाम भविष्य में उतना ही खतरनाक सामने आता है।

मेरी पसंदीदा जर्सी में, मेरे 15 साल

भारत की शुरुआत की वर्षगांठ पर रोहित शर्मा का विशेष संदेश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

15 साल पहले आज ही के दिन भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। 35 वर्षीय ने टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ 23 जून, 2007 को बेलफास्ट में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान खेला था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल पूरे करने पर, रोहित ने सोशल मीडिया पर इस माइलस्टोन पर एक विशेष संदेश साझा किया। रोहित ने इस यात्रा का हिस्सा रहे सभी लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि वह इस यात्रा को जीवन भर संजो कर रखेंगे।

रोहित ने लिखा-₹मेरी पसंदीदा जर्सी में 15 साल सभी को नमस्कार। आज मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के 15 साल पूरे कर रहा हूं जब से मैंने भारत के लिए पदार्पण किया है। यह कैसा सफर रहा है, निश्चित रूप से एक जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगा, ₹मैं बस उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं और उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद जिन्होंने मुझे वह खिलाड़ी बनने में मदद की जो मैं आज हूं,

सभी क्रिकेट प्रेमियों, प्रशंसकों और आलोचकों के लिए टीम के लिए आपका प्यार और समर्थन ही हमें उन बाधाओं से पार दिलाता है, जिनका सामना हम सभी अनिवार्य रूप से करते हैं। धन्यवाद, आरएस रोहित ने एक आधिकारिक बयान में कहा।

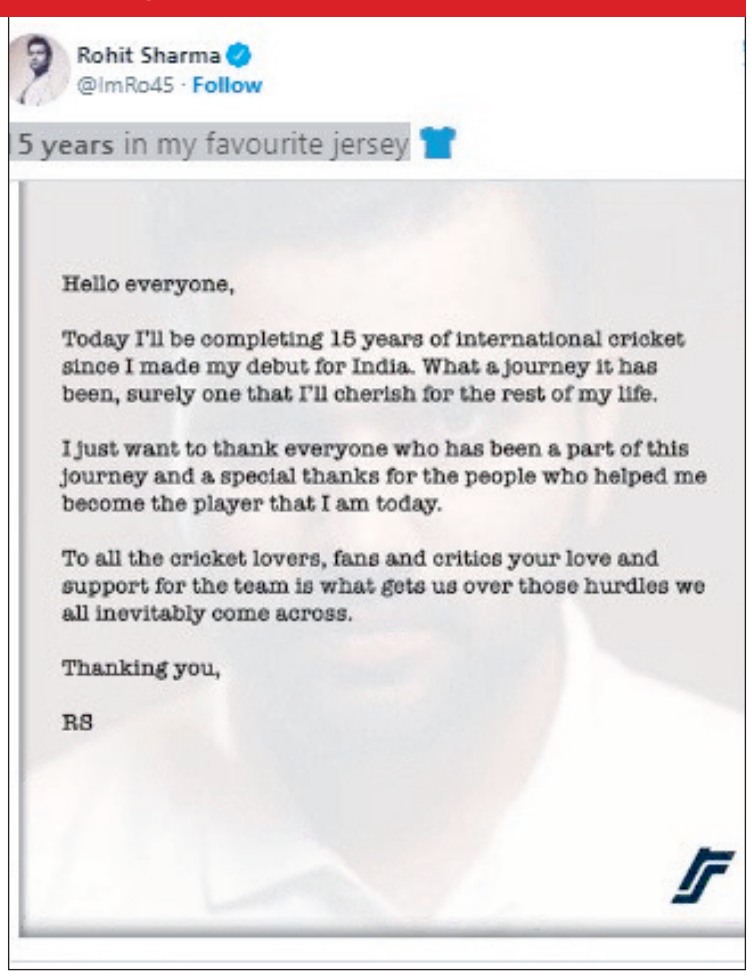

प्रदेशभर में 27 को सत्याग्रह आंदोलन करेगी कांग्रेस

ईडी के मुद्दे को पीछे छोड़ अब प्रदेश कांग्रेस अग्निपथ पर आगे बढ़ेगी। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इस मुद्दे पर पार्टी प्रदेशभर में 27 जून को सत्याग्रह आंदोलन करेगी। इस संबंध में भी एआईसीसी की ओर से दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

23 जून को ईडी में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की पेशी, अग्निपथ योजना और आने वाले दिनों में राष्ट्रपति पद पर होने वाले चुनाव के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। एक दिन पहले ही मंगलवार को विधायक मदन बिष्ट, खुशहाल सिंह अधिकारी, राजेंद्र भंडारी और मयूख महर को छोड़कर सभी विधायक दिल्ली पहुंच गए थे।

इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सांसद प्रदीप टम्टा की भी दिल्ली में मौजूदगी रही। इस दौरान एआईसीसी दफ्तर में वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रदेश के नेताओं से ईडी के मुद्दे को छोड़कर अग्निपथ योजना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के नेता इस योजना के विरोध में उतरे युवाओं का नेतृत्व करें और इस योजना की खामियां जनता तक पहुंचाएं। इसके अलावा आने वाले दिनों में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के संबंध में भी पार्टी नेताओं से एकजुट रहने को कहा गया।

राज्य में अनाथों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड : डॉ0 धन सिंह रावत

जनपद से ब्लॉक तक स्वास्थ्य संवाद स्थापित करेंगे अधिकारी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

प्रदेशभर के अनाथालयों में रह रहे हजारों अनाथों का आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें योजना का लाभ दिया जायेगा, इसके लिये शीघ्र ही बाल विकास विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ सचिव स्तरीय बैठक करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिये स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम के तहत विभागीय उच्चाधिकारी जनपद से ब्लॉक स्तर तक अस्पतालों में जाकर मरीजों से स्वास्थ्य संवाद करेंगे, इसके साथ ही आगामी जुलाई माह में दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जायेगा।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण सभागार देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने राज्यभर के अनाथालयों में रह रहे हजारों अनाथ युवक युवतियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। डॉ0 रावत ने बताया कि सूबे में विभिन्न अनाथालयों में हजारों की संख्या में अनाथ बच्चे एवं युवा रह रहें जिन्हें आयुष्मान योजना का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बाल विकास विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ शीघ्र सचिव स्तरीय बैठक करने के निर्देश दिये ताकि अनाथों को योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। बैठक में डॉ0 रावत ने अधिकारियों को स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम जारी रखने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत विभागीय अधिकारी जिला चिकित्सालयों से लेकर ब्लॉक स्तर के चिकित्सालयों का निरीक्षण कर मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक लेंगे जिसके उपरांत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। विभागीय मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुचाने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से आगामी जुलाई माह में दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमे विभागीय अधिकारियों के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले अनुभवी लोगों के साथ मंथन किया जायेगा। चिंतन शिविर में प्राप्त सुझावों को अमल में लाया जाएगा।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य राधिका झा, चेयरमैन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण डी. के. कोटिया, मिशन निदेशक एनएचएम सोनिका, कुलपति उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रो0 हेमचन्द्र, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा अरुणेंद्र सिंह चौहान, निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मीतू शाह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

धामी सरकार के पास 100 दिन में काम गिनवाने को कुछ नहीं : रविंद्र सिंह आनंद

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सरकार का ध्यान जनहित में कम चुनाव जीतने में ज्यादा आज आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह आनंद ने एक बयान जारी कर भाजपा सरकार के 100 दिन के काम पर हमला बोलते हुए कहा की सरकार के पास कोई एक काम नहीं है जो वह उपलब्धि के तौर पर गिनवा सके ।उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 महीने से अधिक का समय सिर्फ चंपावत चुनाव को कैसे जीता जाए इसमें लगा दिया ,इसके लिए उन्होंने अपने मनपसंद अधिकारियों को चंपावत जिले में तैनात किया एवं पूरा ध्यान चुनाव पर रखा क्योंकि वह चंपावत की लगती हुई सीट खटीमा से 3 महीने पहले ही बुरी तरह हारे थे।

उन्होंने आगे कहा कि पुष्कर धामी का पूरा ध्यान अपनी कुर्सी को बचाने में लगा रहा, ऐसे में वह विकास कार्यों पर क्या ध्यान देते। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से ही धामी सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है । उन्होंने कहा कि जहां चारधाम यात्रा में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई ,वही चार धाम की व्यवस्था देखने को मिली ,यात्रियों को पीने के पानी तक की सुविधाएं ना मिल सकी साथ ही चारधाम श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार तक सरकार दे ना पाई ।

जिस वक्त प्रदेश को धामी सरकार के मंत्रियों की आवश्यकता थी ,उस वक्त धामी सरकार के मंत्री सतपाल महाराज दुबई घूमने चले गए ।जहां एक और घोड़े खच्चर मर रहे थे वहीं दूसरी ओर महाराज जी दुबई में भ्रमण कर रहे थे ।एक और जंगलों में आग लगी हुई थी तो दूसरी ओर धामी सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल मुंबई में सैर सपाटा कर रहे थे उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड वासियों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है क्योंकि चार धाम लोगों की आस्था का केंद्र है और यहां हुई अव्यवस्थाओं का संदेश पूरे विश्व में जाता है ।

उन्होंने कहा की धामी सरकार द्वारा 100 दिन के काम पर लीपापोती एवं कागजी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि जमीन पर काम दिखाने को है नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की राजनीति से बाहर निकल कर प्रदेश की जनता के हित में कुछ काम करने की सोचे, क्योंकि वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने पर ध्यान केंद्रित करने वाली पार्टी रह गई है।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण विश्व विख्यात सिद्ध पीठ बगलामुखी के किए दर्शन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने आज धर्मशाला(हिमाचल प्रदेश) के प्रवासीय दौरे के दौरान कांगड़ा में स्थित विश्व विख्यात सिद्ध पीठ बगलामुखी में परिवार सहित माथा टेका। इस दौरान उनके पति व भारत सरकार में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष ने परिजनों सहित बगलामुखी मंदिर में हवन यज्ञ कर प्रदेश वासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष तीन दिवसीय महिला विधायक सम्मेलन में भाग लेने धर्मशाला में पहुंची हैं। जहां आज विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पति व पुत्र गुरांग एवं पुत्री देवयानी सहित बगलामुखी देवी की विधिवत पूजा अर्चना की। विधानसभा अध्यक्ष ने पूजा-अर्चना करने के बाद कहा कि मां बगलामुखी माता के दर्शन मात्र से ही साधक को अपने जीवन में विद्या, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, आदि सुख की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास एवं समाज की सेवा में वह निरंतर प्रयासरत रहे जिसके लिए शक्ति प्रदान करने हेतु मां बगलामुखी से कामना की है। इसके बाद विधान सभा अध्यक्ष ने धर्मशाला के मैक्लॉडगंज में स्थित बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के नामग्याल मठ के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की।

भाजपा वीरभद्र मंडल की ओर से कार्यसमिति का कार्यक्रम आयोजित

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

भाजपा वीरभद्र मंडल की ओर से कार्यसमिति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री व क्षेत्रीय विधायक डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को भी याद किया गया।

मालवीय नगर स्थित दुर्गा मंदिर में आयोजित कार्यसमिति का शुभारंभ डॉ अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉ अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवार वाद पर विश्वास करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि एक संगठन है और इसका हर कार्यकर्ता इस संगठन की ताकत है। आज हमारे संगठन की ही शक्ति है कि भाजपा देश मे ही नहीं अपितु विश्व में सबसे बड़े राजनैतिक दल के रूप में उभरकर आयी है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ताओ की ही मेहनत व नीतियों का परिणाम है कि आज राज्यसभा में हमारे सांसदों की संख्या सौ से ज्यादा हो गयी है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर प्रदेश की पार्टी है यही कारण है कि हम आज इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए हैं। डॉ अग्रवाल ने कहा कि आप सभी आम कार्यकर्ता नहीं है बल्कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। देवतुल्य कार्यकर्ताओं की यही खासियत है कि वह हर परिस्थितियों में ढाल बनकर खड़ा रहता है। लगातार चौथी व बम्पर वोटों से जीत को उन्होंने कार्यकर्ताओं की जीत बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सम्मान में कहा कि आप वह फ़ौज है जिनके आगे कोई टिक नहीं सकता। आपके आशीर्वाद से वह विधायक बने है और दुवाओं से मंत्री।इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता संजय शास्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किए जाएंगे। कहा कि हमारे प्रधानमंत्री देश ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। जनता को उनकी नीति, नीयत, कार्यों का पूर्ण विश्वास है और विपक्ष का षड्यंत्र और दुष्प्रचार उस विश्वास को हिला भी नहीं पाया।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र प्रथम के उद्घोष के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सफल प्रयास का मंत्र विकास की नकारात्मक राजनीति पर भारी पड़ा है।

इस मौके पर मंडल अध्यक्ष वीरभद्र अरविंद चौधरी, महामंत्री व पार्षद सुंदरी कंडवाल, महामंत्री सुरेंद्र सिंह, अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार भारती, युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय जुगरान, मनीष मैठाणी, शशि सेमल्टी, अविनाश सेमल्टी, उषा लखेड़ा, वायुराज, रमेश चंद शर्मा, निर्मला उनियाल, गुंजन शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 50 नए संक्रमित मिले, देहरादून में सबसे अधिक मामले

यूज़ वायरस नेटवर्क

प्रदेश में फिर कोरोना की रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई है। बुधवार को कोरोना के 50 नए संक्रमित मिले हैं, इसमें देहरादून के सर्वाधिक 29 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, बुधवार को सामने आए 50 नए मामलों में देहरादून के 29 मामलों के अलावा चमोली, हरिद्वार व नैनीताल के तीन-तीन मामले, पौड़ी व उत्तरकाशी के दो-दो मामले और टिहरी व ऊधमसिंह नगर के चार-चार मामले शामिल हैं।

20 कोविड संक्रमित मरीज बुधवार को स्वस्थ हो गए। अब प्रदेश में कुल 194 कोविड के एक्टिव केस हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 140 मामले देहरादून के हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पर 13 मामलों के साथ हरिद्वार और तीसरे नंबर पर 11 मामलों के साथ नैनीताल के नाम शामिल हैं।

चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। दूसरी ओर, बुधवार को प्रदेश में 7288 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों से वैक्सीनेशन कराने के साथ ही कोरोना बचाव की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है।

बुधवार को 24 घंटे के भीतर जिले में 29 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमित पाए गए लोग जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से हैं। बुधवार को कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 140 पहुंच गई। बुधवार शाम राज्य कोविड कंट्रोल रूप से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, प्रदेशभर में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमण के 50 नए मामले सामने आए हैं। इसमें देहरादून जिले में सर्वाधिक 29 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 24 घंटे की अवधि में जिले में 369 मरीजों के नमूने कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं।

पूर्व में भेजे गए नमूनों में से 415 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। अभी 52 नमूनों की रिपोर्ट आनी बाकी है। इस साल एक जनवरी से अब तक जिले में 33,460 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. राजीव दीक्षित ने बताया कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। डॉ. दीक्षित ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। उन्होंने बताया कि कोरोना के लक्षण नजर आने पर अस्पताल में जाकर जांच कराएं।

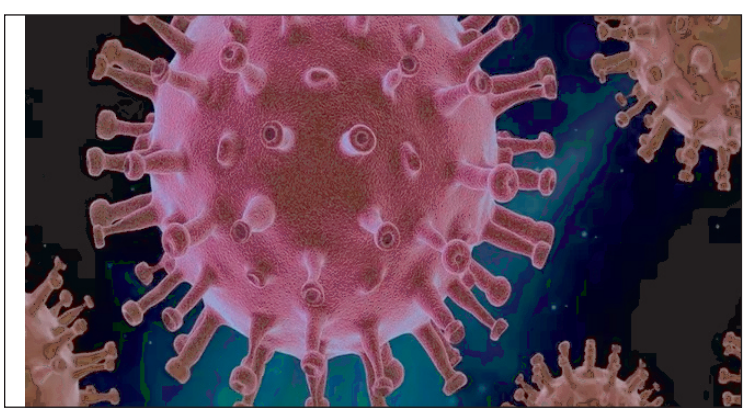

संपादकीय

राज्यों पर बढ़ता कर्ज

देश के दस राज्य भारी कर्ज के दबाव में हैं और इससे उनकी वित्तीय स्थिति असंतुलित हो सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि इन राज्यों में सभी सूचक निराशाजनक संकेत दे रहे हैं. इनमें सबसे खराब स्थिति पंजाब की है, जहां 2026-27 में कर्ज और राज्य के सकल घरेलू उत्पादन (एसजीडीपी) का अनुपात 45 प्रतिशत से अधिक हो जाने का अनुमान है. इस अवधि तक राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल में यह अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक हो सकता है. देश के केंद्रीय बैंक ने अपने अध्ययन में कहा है कि वित्तीय स्थिति को और ज्यादा डगमगाने से बचाने के लिए ठोस उपाय किये जाने चाहिए. इन राज्यों को अपने कर्ज स्तर को स्थिर करने को प्राथमिकता देनी चाहिए. इस अध्ययन में पाया गया है कि देश के दस राज्यों पर सबसे अधिक कर्ज का बोझ है. ये राज्य हैं- पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा. पूरे देश की सभी राज्य सरकारें जितना खर्च करती हैं, उसका लगभग आधा इन दस राज्यों में खर्च किया जाता है. आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब ने वित्तवर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित कर्ज और वित्तीय घाटे के लक्ष्यों को भी पार कर लिया. केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक कर्ज लिया, तो मध्य प्रदेश का वित्तीय घाटा तय हिसाब से ज्यादा रहा. हरियाणा और उत्तर प्रदेश लक्ष्यों के भीतर ही कर्ज और वित्तीय घाटे को रख सके. रिजर्व बैंक का आकलन है कि राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल वर्तमान वित्तवर्ष 2022-23 में कर्ज और वित्तीय घाटे के लक्ष्य को लांघ सकते हैं. राज्यों द्वारा कर्ज लेने का मुख्य कारण यह होता है कि उनकी राजस्व प्राप्तियां और केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि से उनका खर्च पूरा नहीं होता. ऐसे में वित्तीय घाटा भी बढ़ जाता है. मध्य प्रदेश, पंजाब और केरल की करों से होने वाली अपनी राजस्व प्राप्तियों में लगातार कमी आ रही है. पहले उल्लिखित दस राज्यों में से अधिकतर में गैर-कर राजस्व में भी गिरावट आ रही है. इस स्थिति में ये राज्य अपने राजस्व का 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा खर्च करने के लिए विवश होते हैं. ऐसे में खर्च की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक असर पड़ता है और पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाता. यह जो खर्च होता है, उसका बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने, पेंशन देने और प्रशासनिक खर्च में चला जाता है. ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि विकास कार्यों पर खर्च के लिए कम रकम बचती है. रिपोर्ट ने रेखांकित किया है कि अन्य राज्यों से इन दस राज्यों में विकास कार्यों पर खर्च बहुत कम है. यदि इन राज्यों ने राजस्व बढ़ाने तथा कर्ज कम करने पर जोर नहीं दिया, तो अर्थव्यवस्था पर खराब प्रभाव पड़ेगा और विकास की गति धीमी हो जायेगी. रिजर्व बैंक के अध्ययन से निकले संदेश पर गौर करना चाहिए.

उत्तराखंड में पहली बार कोई आईएएस गया जेल

13 घंटे पूछताछ के बाद यादव को न्यायिक हिरासत में लिया गया

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

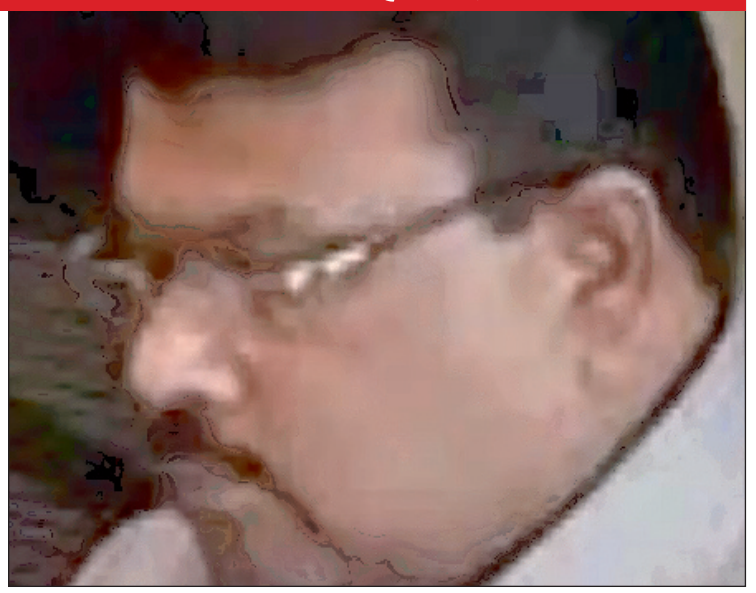

विजिलेंस दफ्तर में करीब 13 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आईएएस रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यादव ने किसी भी सवाल का वाजिब जवाब नहीं दिया है।

इसके लिए विजिलेंस उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) भी मांगेगी। इसके लिए न्यायालय में बाद में प्रार्थनापत्र दिया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आरोपी आईएएस(निलंबित) रामविलास यादव बुधवार को ढाई साल के बाद विजिलेंस के सामने पेश हुए थे। इस मामले में डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा ने बताया कि उन्होंने विजिलेंस अफसरों के किसी भी सवाल का वाजिब जवाब नहीं दिया। उनकी पत्नी को भी वहां पर बुलाया गया लेकिन उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया। उनसे बुधवार देर रात करीब दो बजे तक पूछताछ की गई। इसके बाद 2.15 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद यादव को बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे विजिलेंस कोर्ट में पेश किया गया। उनके वकीलों ने ज्यूडिशियल कस्टडी रिमांड (न्यायिक अभिरक्षा) का विरोध किया। लेकिन, विजिलेंस की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर उन्हें सुद्धोवाला जेल ले जाया गया। शाम करीब साढ़े सात बजे उन्हें जेल में दाखिल किया गया।

अकड़ में बोले हम कुछ नहीं बोलेंगे

रामविलास यादव यूपी के जमाने से ही राजनीतिक लोगों में खासी पैठ रखते थे। इसी बात का गुमान था कि वह अक्सर कहते थे कि उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन, 2017 में उत्तराखंड आते ही यूपी सरकार ने उनके खिलाफ जांच कराने की संस्तुति कर दी थी। ढाई साल बाद विजिलेंस के सामने पेश हुए। उन्हें जवाब नहीं दिया। बृहस्पतिवार को जब उन्हें कोर्ट लाया गया तब भी उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अकड़ में बोला कि हम कुछ नहीं बोलेंगे।

उत्तराखंड में पहली बार कोई आईएएस गया जेल

उत्तराखंड के 22 वर्षों के इतिहास में तमाम आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनकी विभिन्न एजेंसियों ने जांच भी की है। लेकिन, यह पहला मौका है जब कोई आईएएस गिरफ्तार हुआ और फिर उसे जेल भेजा गया। इससे पहले एक पूर्व आईएएस भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त जरूर किए जा चुके हैं।

असम बाढ़ : 12 नई मौतों की संख्या और बढ़कर 101 हुई, 54 लाख से अधिक प्रभावित

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

गुवाहाटी : अधिकारियों ने बताया कि असम में गुरुवार को बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और 54.5 लाख से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं और 12 लोगों की मौत की खबर है।अधिकांश प्रभावित जिलों में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ उफान पर हैं और राज्य के कुल 36 जिलों में से 32 जिलों में भूमि का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है।बुलेटिन के अनुसार, दिन के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों द्वारा राज्य भर में 276 नावों की मदद से कुल 3,658 लोगों को निकाला गया।एक अधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ ने असम के 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में 14,500 से अधिक फंसे हुए लोगों को बचाया है।एनडीआरएफ की पहली बटालियन आपदा प्रतिक्रिया बल ने प्रभावित जिलों में बचाव अभियान शुरू किया और भारी बाढ़ वाले जिलों में 70 से अधिक नावों और 400 जवानों को तैनात किया, इसके सहायक कमांडेंट संतोष कुमार सिंह ने पीटीआई को बताया।उन्होंने कहा कि 207 कर्मियों वाली अन्य बटालियनों की आठ अतिरिक्त टीमों को मंगलवार से सिलचर भेजा गया है।एनडीआरएफ द्वारा कामरूप, कामरूप ग्रामीण, बोंगाईगांव, बारपेटा, बजली, होजई, नलबाड़ी, दरंग, तामूलपुर, नगांव, उदलगुरी और कछार में बचाव अभियान चलाया जा रहा है।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा घाटी में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार को सिलचर का दौरा करने वाले हैं। राज्य के 32 जिलों में कुल जनसंख्या 54,57,601 प्रभावित हुई।कामरूप जिले में बाढ़ से 218 सड़कें और 20 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इसके अलावा दो तटबंध टूट गए हैं। 99,026 हेक्टेयर का फसल क्षेत्र और 33,17,086 जानवर प्रभावित हुए हैं।राहत शिविरों में शरण नहीं लेने वाले बाढ़ प्रभावितों के बीच 1026 डिलीवरी पॉइंट से राहत सामग्री वितरित की गई।

बातचीत से सुलझाया जाए यूक्रेन मामला, आतंकवाद के लिए न हो अफगान जमीन का इस्तेमाल

नई दिल्ली, एजेंसी। चीन में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में आज घोषणापत्र जारी किया गया। इसमें खास तौर पर रूस-यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र करते हुए बातचीत से मामला सुलझाने पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है, हम सभी राज्यों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतभेदों, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं।

घोषणापत्र में कहा गया है कि ब्रिक्स देश रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहा गया है कि हम इसकी संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर देते हुए एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का पुरजोर समर्थन करते हैं। किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने या प्रशिक्षित करने के लिए अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने हिस्सा लिया। घोषणापत्र में कहा गया कि हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संवाद और परामर्श के माध्यम से देशों के बीच मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता पर बल देते हैं। संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी अनुकूल प्रयासों का समर्थन करते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच जारी गतिरोध और यूक्रेन पर रूसी हमले के मद्देनजर मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का संदर्भ महत्वपूर्ण है। घोषणापत्र में कहा गया कि हमने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की और यूएनएससी तथा यूएनजीए जैसे उपयुक्त मंचों पर व्यक्त की गई अपनी राष्ट्रीय रुख को दोहराया। हम रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करते हैं। ब्रिक्स ने कहा कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल देते हुए एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का पुरजोर समर्थन करता है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि 'ब्रिक्स' ने मौजूदा वैश्विक संकट में मुश्किलों से उबरने की क्षमता और ऊर्जा दिखाई है। साथ ही उन्होंने संभवतः अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए पांच सदस्यीय समूह से एकपक्षीय प्रतिबंधों के दुरूपयोग का विरोध करने की अपील की। शी ने वीडियो लिंक के जरिये 14वें ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा कि पिछले साल विश्व द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रसार, विश्व अर्थव्यस्था के उबरने में मशक्कत करने और शांति एवं सुरक्षा के मुद्दों का सामना करना जारी रहा।

डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला सांसद ने पेश किया भारत विरोधी प्रस्ताव, पारित होने की उम्मीद नहीं

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी संसद के निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर ने भारत विरोधी तेवर जारी रखते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें विदेश मंत्री से धार्मिक आजादी के कथित उल्लंघन के लिए भारत को विशेष रूप से चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की गई है। हालांकि इस प्रस्ताव के पारित होने की उम्मीद नहीं है।

सांसद रशीदा तालिब व जुआन वर्गास द्वारा सह-प्रायोजित, प्रस्ताव में बाइडन प्रशासन से अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया गया है, जिसने लगातार तीन वर्षों तक भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की।

यह प्रस्ताव आवश्यक कार्रवाई के लिए सदन की विदेश मामलों की समिति के पास भेज दिया गया है। सांसद उमर ने भारत के मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया है। भारत से जुड़ी कई सुनवाइयों में भी उमर ने भारत विरोधी रुख दिखाया है।

उमर द्वारा प्रस्ताव पेश करने से पहले भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में उसकी आलोचना को खारिज करते हुए कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी 'वोट बैंक की राजनीति' की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत पर यह रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है। भारत ने उमर की पीओके यात्रा की भी निंदा की थी। भारत ने इस यात्रा को देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए उनकी 'संकीर्ण मानसिकता' वाली राजनीति कहा था।

व्हाइट हाउस प्रवक्ता केरिन ज्यां-पियरे ने कहा, राष्ट्रपति जो बाइडन का मानवाधिकारों व लोकतंत्र के महत्व पर स्पष्ट रुख है। उन्हें इन मामलों में विश्व नेताओं से सीधे तौर पर बात करने में कोई परेशानी नहीं है। पियरे से पूछा गया था कि क्या बाइडन पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणियों के बाद भारत में हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर बात करेंगे। बाइडन इस्राइल यात्रा के दौरान मोदी और यूएई के राष्ट्रपति से डिजिटल माध्यम से मुलाकात कर सकते हैं। पियरे ने यह नहीं बताया कि उनकी चर्चा के मुद्दे क्या होंगे।

देश का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बना यूपी वैश्विक महामारी के बावजूद बढ़ा 30 फीसदी निर्यात

लखनऊ, एजेंसी।कोरोना काल की चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश ने निर्यात के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है। यूपी अब देश का पांचवां बड़ा निर्यातक प्रदेश बन गया है। निर्यात के क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ही यूपी से आगे हैं। 2021-22 में प्रदेश से 1,55,897 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है जो 2020-21 की तुलना में तीस फीसदी ज्यादा है।

2020-2021 में प्रदेश से 121,140 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था जो 2021-22 में बढ़कर 155897 करोड़ हो गया। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 2017 में योगी सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और प्रदेश को एक खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा था।

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति बनाई और एनओसी की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। बड़े निवेशकों के लिए अलग से व्यवस्था की गई। इस सबके साथ प्रदेश की छवि बदलने के लिए कानून-व्यवस्था और विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं पर खास फोकस किया। इसी का परिणाम है कि अब तक हुई तीन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कुल 2,08,994 करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में आया है।

दैनिक
न्यूज वायरस
न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।
सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002
email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094
वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा